Volume 1, Issue 1 June 2015 ISSN NO: 2454 - 2326

North Asian International Research Journal Consortium

North Asian International Journal Of Multidisciplinary

Chief Editor
Dr. Nisar Hussain Malik

Publisher
Dr. Bilal Ahmad Malik

Associate Editor
Dr.Nagendra Mani Trapathi

Honorary
Dr.Ashak Hussain Malik

Welcome to NAIRJC

ISSN NO: 2454 - 2326

North Asian International Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi, Urdu all research papers submitted to the journal will be double-blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in Universities, Research Institutes Government and Industry with research interest in the general subjects

Editorial Board

J.Anil Kumar
Head Geography University of Thirvanathpuram

Kiran Mishra
Dept. of Engligh,Ranchi University, Jharkhand

R.D. Sharma
Head Commerse & Management Jammu University

Manish Mishra
Dept. of Engg, United College. (ALD)

Tihar Pandit
Dept. of Environmental Science, University OF Kashmir.

Neelam Yaday
Head Management MAT.K.M Patel College Thakurlie, Mumbai University.

Ashiq Mallik
Head Pol-Science G.P, PG College (ALD) Kanpur University

Sanjuket Das
Head Economicsn Samplpur University

Somanath Reddy
Dept. of Social Work, Gulbrga University.

R.P. Pandday
Head Education Dr. C.V.Raman University

K.M Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Simnani
Dept. of Poltical Science, Govt. Degree College, University of Kashmir.

Nisar Hussain
Dept. of Mdicine A.I. Medical College (U.P)

Khagendra Nath Sethi
Head Dept. of History Sambalpur University.

B.S.A.U
Dept. of Commerce, Aruganbad

Rajpal Choudhary
Dept. Govt. Engg. College Bikaner (Raj)

Rayaz Ahmad
Dept. of Botany Govt. Degree College Shopian. Kashmir University

Ravi Kumar
Director, H.I.M.T, Allahabad

Ashok D. Waga
Dept. of Accountancy, B.B.N. College Thana

M.C.P. Singh
Head Information Technology Dr C.V. Rama University

Rama Singh
Dept. of Poltical Science A.K.D.C. Allahabad, Uni. of (ALD)

Address: - Ashak Hussain Malik House No. 221 Gangoo, Pulwama, Jammu and Kashmir, India - 192301, Cell: 09086405302, 09906662570, Ph. No: 01933-212815,
Email: nairjc5@gmail.com Website: www.nairjc.com

A Peer Reviewed Refereed Journal

मादक पदार्थों की तस्करी और भारतीय सुरक्षा:

*Arvind kumar

*Research scholar, Department of Defence and strategic studies University of Allahabad, (Allahabad)

नारकोटिक तस्करी, घटना, जो एक संगठित सीमा पार अपराध के रूप में शुरू हुई थी, अब आतंकवादी समूहों के साथ इसके पैशाचिक गठबंधन के कारण राष्ट्रराज्यों के लिए एक खतरा बनकर उभरी है। गोल्डन क्रिसेंट अवैध अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अकेले अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने 1999 में कुल अवैध उत्पादन का लगभग 6000 मीट्रिकटन साझा किया। यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये दवाएं इस देश में पाक प्रायोजित आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत हैं। और इसलिए भी कि भारत अंतरराष्ट्रीय दवा उद्योग के लिए अफीम का एकमात्र वैध आपूर्ति कर्ता है, जो निर्यात से राजस्व के रूप में लगभग 209 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष (1999) उत्पन्न करता है। पाक-अफगान सीमा की अर्थव्यवस्था अफीम और भांग के उत्पादन पर निर्भर है। नशीली दवाओं का पैसा असंगठित लेकिन व्यवस्थित तरीके से भारतीय मुद्रा बाजार में प्रवाहित किया जा रहा है जिससे वित्तीय संस्थानों को नुकसान हो रहा है। इसलिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा है। जाहिर है, यह कार्रवाई के लिए बहुत देर होने से पहले नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों दोनों से गंभीरता से विचार करने की मांग करता है।

नार्को-आतंकवाद नशीले पदार्थों और आतंकवाद के बीच सांठगांठ को संदर्भित करता है। यह पत्र दोनों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं और भारत की सुरक्षा के लिए इसके प्रभावों की जांच करता है। चूँकि भारत में आतंकवाद के स्रोत घरेलू सीमाओं से परे हैं, यह अध्ययन पाकिस्तान में अवैधनशी ले पदार्थों के व्यापार में वृद्धि पर भी प्रकाश डालता है, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एन डब्ल्यू एफ पी दुनिया में अफीम के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी रकम पैदा करते हैं। नशीली दवाओं की आय का उपयोग पाकिस्तान सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत को अस्थिर करने के लिए किया जाता है।।

आतंकवाद को प्रायोजित करना एक महंगा मामला है और हत्या, अपहरण और तोड़फोड़ के लिए पैसा उचित माध्यमों से नहीं आता है। यह अवैध और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से आता है। मादक दवाओं का बाजार मूल्य दुनिया के किसी भी उपभोक्ता उत्पाद की तुलना में बहुत अधिक है। इससे बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है और वह भी नगदी के रूप में। उदाहरण के लिए, गोल्डन क्री सेंट की एक किलो ग्राम हेरोइन जिसकी की मत दक्षिण एशिया में लगभग एक लाख रुपये है, अमेरिकी बाजार में लगभग एक करोड़ रुपये में मिलती है। यह आंकड़ा स्थान से भिन्न होता है, जो आगे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। गोल्डन क्री सेंट से उत्पन्न होने वाली हेरोइन की कीमत रुपये से लेकर है। 30 लाख से रु। [1] करोड़ प्रतिकिग्रा.1

गौरव तलब है कि पाकिस्तानी हेरोइन और को लंबियाई मारिजु आना अमेरिका और यूरोपीय देशों में सबसे अधिक मांग वाली मादक दवाएं हैं। [2] पश्चिम में इन दवाओं से जितना पैसा पैदा होता है वह आश्चर्य जनक है। यह अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल भारी धन के कारण है कि आतंकवादियों ने 'ऑपरेशन आतंकवाद' के खर्चों को पूरा करने के लिए मादक पदार्थों के तस्करों, तस्करों और अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संबंध स्थापित कि एहैं।

नार्को-आतंकवाद शब्द का पहली बार अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था जब बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, निकारागुआ और अन्य मध्य अमेरिकी देशों में ड्रग तस्करों ने एक पेशे के रूप में अवैध व्यापार का आयोजन किया और एक समानांतर सरकार चलाई। ये देश भारी मात्रा में कोकीन और भांग का उत्पादन करते हैं। दरअसल, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कोकीन और भांग की खेती और उत्पादन पर निर्भर करती है। पड़ोसी देश होने के अलावा अमेरिका नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार है। ड्रग एडिक्ट्स की बढ़ती आबादी ने अमेरिकी सरकार को स्थिति का जवाब देने के लिए मजबूर किया। हालाँकि, इसकी अनुभूति बहुत बाद में हुई, जब राष्ट्रपति रीगन ने 1980 के दशक के दौरान लैटिन अमेरि की देशों में वामपंथी आंदोलनों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। इस अवधि के दौरान पहली बारनार्को-आतंकवाद एक मुद्दा बना। [3]

तस्करीऔरआतंकवाद

यहपरिकल्पनाकिनशीलेपदार्थोंकीतस्करीआतंकवादीगतिविधियोंकोधनमुहैयाकरातीहै, कोतार्किकस्पष्टीकरणकीआवश्यकताहैऔरयहतर्ककुछतथ्योंऔरआंकड़ोंपरआधारितहै। ये़हैं:

1. मादक पदार्थ उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर निर्भर है। जब तक उनके पास एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था नहीं होगी, सख्त कानून के बावजूद अवैध मादक पदार्थों का व्यापार जारी रहेगा।
2. अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा अवैध अफीम उत्पादक (4,600 प्रतिवर्ष, 1999 दुनिया के कुल 6000 मीट्रिक टन) देश है। अफगानिस्तान के कुल 31 प्रांतों में से 18 प्रांतों में अफीम की खेती की जाती है। [4] खेती तालिबान नियंत्रित प्रशासन के तहत एक संगठित रूप में की जाती है।
3. नारकोटिक ड्रग्स सबसे आकर्षक वस्तु है जो बिना कागजी कार्रवाई के तुरंत पैसा कमाती है। व्यापारिक लेन-देन हार्ड कैश में किया जाता है और कानूनी कार्रवाई के लिए साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज नहीं छोड़ा जाता है।
4. नशीली दवाओं की आय को कई कानूनी और अवैध वित्तीय संस्थानों और छोटे व्यावसायिक उद्यमों के माध्यम से लूटा जाता है।
5. आतंकवाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है। चूंकि आधिकारिक और कानूनी स्रोतों से उस राशि को हासिल करना मुश्किल है, इसलिए आतंकवादी ड्रग सिंडिकेट औरअंडर वर्ल्ड डॉन से सहयोग के लिए संपर्क करते हैं।
6. आपराधिक सरगनाओं और नशीली दवाओं के तस्करों को भी प्रस्ताव आकर्षक लगता है क्यों कि यह उन्हें राजनीतिक सत्ता के आकांक्षी (आतंकवादियों) के साथ सहयोग करने का अवसर देता है और इस तरह उन्हें समय के साथ राजनीति में प्रवेश देता है। राजनीति का अपराधीकरण उसी गठजोड़ का परिणाम है।
7. पाकिस्तानी ड्रग सिंडिकेट भारत को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठानों की मिली भगत से समानांतर अर्थव्यवस्था चलाता है। [5] यूएनडीसीपी की रिपोर्ट के अनुसार टर्न ओवर के मामले

में पाकिस्तान का हेरोइन उद्योग लगभग रु.74 अरब यानी 1992-93 के अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत, जो कुल अनुमानित छाया अर्थव्यवस्था का 20-25 प्रतिशत है। यह भी रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान ने 1992 में हेरोइन के निर्यात से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। [6]

ये कुछ महत्व पूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर नशीले पदार्थों और आतंकवाद के बीच गठजोड़ और भारत के खतरे की धारणा की जांच की जा सकती है। चूंकि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद का तात्कालिक स्रोत है, इसलिए पाकिस्तान में मादक पदार्थों की तस्करी के परिदृश्य और राजनीति, सेना और अंडरवर्ल्ड संचालकों, मुख्य रूप से मादक पदार्थों के सिंडिकेट के साथ इसके पैशाचिक गठबंधन की जांच करना प्रासंगिक है। पाकिस्तान में यह ना पाकगठबंधन भारत की सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय है।

पाक-अफगानिस्तान सीमा पर अनादि काल से आदिवासियों के लिए नारकोटिक्स आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। यह 1978 तक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्या के रूप में सामने नहीं आई। इस क्षेत्र में उत्पादित अफीम का स्थानीय स्तर पर उपभोग किया जाता था। न तो किसी ने इसकी परवाह की और न ही इसे खतरे के रूप में सोचा। समस्या अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के साथ शुरू हुई और उसके बाद यूएस-पाक संयुक्त प्रति-हस्तक्षेप हुआ। जिया-उल-हक की सैन्य तानाशाही के दौरान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए अफीम और भांग की खेती को प्रोत्साहित किया गया था। नशीली दवाओं की खेती के लिए जनरल जिया के समर्थन ने भारत में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को एक नया आयाम दिया। उनका लक्ष्य भारत को अस्थिर करना था।

लेकिन इस प्रक्रिया में वह पाकिस्तान पर इसके नतीजों का अनुमान लगाने में विफल रहे। उनके मार्शल प्रशासन के दौरान हेरोइन की लत एक महामारी की तरह फैल गई। यूएनडीसीपी की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि 1993 में पाकिस्तान में 1.5 से 1.9 मिलियन ड्रग एडिक्ट थे । [7] शासन, जो अपने सख्त हाथ के लिए लोकप्रिय था, ने पेशावर, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हेरोइन और हशीश के मुफ्त वितरण को नियंत्रित नहीं किया। जहां ये दवाएं उनकी शुद्धता के आधार पर 15 से 60 रुपये प्रति पैकेट सस्ते में उपलब्ध थीं। [8] इस समय के दौरान नशीली दवाओं के तस्कर स्वतंत्र रूप से काम करते थे और थोड़े समय के भीतर ही अरबपति बन गए और खुद को लैटिन अमेरिकी ड्रग बैरन की तर्ज पर सिंडिकेट के रूप में संगठित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में मादक दवाओं के उत्पादन और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्त पोषित राजनीतिक दलों, आर्थिक मंचों और रिश्वत अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया।

मादक पदार्थों की तस्करी में जनरल ज़िया की संलिप्तता उनकी मृत्यु के बाद ही सामने आई जब

नारकोटिक्स राज्य मंत्री मियां मुजफ्फर शाह ने खुलासा किया कि जनरल जिया के संरक्षण में पाकिस्तानी ड्रग सिंडिकेट बढ़े। 1984 में ओस्लो के फोरनेबु हवाई अड्डे पर नार्वे की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के ड्रग तस्कर रज़ा कुरैशी ने ज़िया के ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश किया। नॉर्वेजियन पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिकों के तीन नामों का खुलासा किया- ताहिर बट, मुनव्वर हुसैन और हामिद हुसैन जिन्हें जनरल जिया का संरक्षण प्राप्त था। [9] नॉर्वेजियन पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया और इन तीनों को नशीली दवाओं के अपराधों के लिए दोषी ठहराया। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उनके राजनीतिक संबंधों के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अंत में, जब नार्वेजियन सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत की और राजनयिक कार्रवाई की धमकी दी, तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

आईएसआई, सेना और नारकोटिक्स :

आईएसआई पाकिस्तान में खुफिया सेवाओं की कुंजी है। यह राजनीतिक प्रभाव रखता है और निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण सेल है। यह फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के रूप में जानी जाने वाली सैन्य खुफिया जानकारी के सहयोग से संचालित होता है। इसके महत्व का विश्लेषण इस तथ्य से किया जा सकता है कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख हामिद गुल ने इस्लामी जहमुरी इत्तेहाद नामक एक राजनीतिक पार्टी शुरू की, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके उम्मीदवार राज्य और राष्ट्रीय विधानसभाओं के सदस्य बन गए। सेना और खुफिया सेवाओं का ड्रग कनेक्शन तब सामने आया जब पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ओकले के कहने पर बेनजीर ने बीसीसीआई के घोटाले की जांच का आदेश दिया। पूरी कवायद आंखों में धूल झोंक गई जब मिर्जा इकबाल बेग को अपनी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत के बावजूद जमानत पर रिहा कर दिया गया। माना जाता है कि बेनजीर सेना और आईएसआई के दखल का सामना नहीं कर सकीं। एक अमेरिकी विद्वान, सेलिग हैरिसन ने ठीक ही कहा था कि पाकिस्तान के पास सेना में बहुत ऊपर दस नोरिएगा हैं और उनके नामों का खुलासा करना बहुत मुश्किल था। [13] मादक दवाओं, सेना और खुफिया जानकारी के इस अपवित्र गठबंधन की उत्पत्ति 1978 में हुई जब अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के खिलाफ अपना युद्ध अभियान शुरू किया। अमेरिकी विश्लेषक अब इस क्षेत्र में नार्को-आतंकवाद की समस्या के प्रति जाग गए हैं। वे 1970 और 80 के दशक के दौरान सोवियत विस्तारवाद के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। वास्तव में अमेरिकी सरकार ने सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन के लिए धन जुटाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी को प्रोत्साहित किया। डीईए को 1980 के दशक के दौरान आदेश द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने कार्यालयों को बंद करना पड़ा। CIA के पास क्षेत्र की पूरी कमान थी और उसने जानबूझकर अवैध ड्रग्स के व्यापार को फलने-फूलने दिया।

अफीम की उपजाऊ जमीन में आईएसआई और सेना के नशे का कनेक्शन हो गया। NWFP की राजधानी लांडी कोटाल अफीम, हेरोइन और हथियारों के व्यापार लेनदेन का मुख्य केंद्र है। आधिकारिक तौर पर लैंडी कोटाल, जमरुद, बारा, दर्रा आदम खेल और अफीम उगाने वाले पूरे क्षेत्र में अफीम के बाजार पाकिस्तान का हिस्सा

हैं। व्यवहार में स्थिति समान नहीं है। NWFP स्थानीय जनजातियों के सीधे अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसे- अफरीदी, खटाके, वज़ीर, ओरकजई, बंगगाश, तुरीस और मसूद। ड्रग्स और बंदूकें उनके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन का हिस्सा हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि मादक पदार्थ उनकी आय का मुख्य स्रोत है, जिसे एक संगठित नेटवर्क में आदिवासी प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। पाकिस्तान सरकार अगर उनके स्थानीय मामलों में दखल देगी तो परेशानी को न्यौता देगी। [15] इसलिए, यह आईएसआई और सेना के माध्यम से नियंत्रण रखता है, जिनकी उपस्थिति ने इस क्षेत्र में जनजातीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लाए हैं। आईएसआई एजेंटों और सेना के जवानों की मदद से हेरोइन के उत्पादन के लिए कई रिफाइनरी स्थापित की गईं, जिसकी पश्चिमी बाजार में काफी मांग है। जब से आईएसआई और सेना तस्वीर में आई है, तब से इस क्षेत्र में अफीम शोधन तकनीक अधिक परिष्कृत हो गई है। गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार के लिए लैंडी कोटल और डेरा में शोधन प्रयोगशालाओं के लिए चीनी रसायनज्ञों को काम पर रखा गया था। डीईए ने यह भी पुष्टि की कि 1981 तक, चीनियों ने इस क्षेत्र में शोधन प्रयोगशालाओं में खुद को स्थापित कर लिया था। [16] तथ्य यह है कि अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हेरोइन की बाढ़ आ गई है, इस क्षेत्र में दवा उद्योग के विकास पर जोर देता है। यह आईएसआई और सेना के सहयोग के बिना संभव नहीं था।

भारत में आतंकवाद को वित्त पोषण :

आतंकवाद के वित्तपोषण के स्रोतों को ट्रैक करने की आवश्यकता 1986 में महसूस की गई थी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1986 में भाड़े के सैनिकों की भर्ती, उपयोग, वित्त और प्रशिक्षण के खिलाफ एक समझौते का मसौदा तैयार किया था। इस सम्मेलन को दिसंबर में मतदान के बिना अपनाया गया था। 4, 1989। सम्मेलन के अनुच्छेद 5 में इस बात पर जोर दिया गया है कि सदस्य राज्य 'भाड़े के सैनिकों की भर्ती, उपयोग, वित्त या प्रशिक्षण नहीं देंगे'। इसके अलावा 1994 में महासभा ने मादक पदार्थों के तस्करों और भाड़े के सैनिकों के बीच बढ़ते संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन प्रस्तावों को याद करते हुए, आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर, 1999 को बिना वोट के अपनाया गया था। इस सम्मेलन को लागू करने के लिए 22 सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसमर्थन के लिए 20 जून को सम्मेलन को पहले ही मंजूरी दे दी है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आतंकवाद के वित्तपोषण को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में स्थापित करता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आतंकवाद का कोई कार्य वास्तव में किया जाए। सम्मेलन यह स्पष्ट करता है कि हर बार जब पैसा किसी राज्य पार्टी के क्षेत्र से गुजरता है, तो एक अंतरराष्ट्रीय अपराध किया जाता है, जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह यह भी स्वीकार करता है कि अफीम के उत्पादन और छोटे हथियारों के व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों से आय एक अंतरराष्ट्रीय 'शो बैंकिंग' प्रणाली के माध्यम से आतंकवादियों के हाथों में जाती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आतंकवाद का कोई कार्य वास्तव में किया जाए। सम्मेलन यह स्पष्ट करता है कि हर बार जब पैसा किसी राज्य पार्टी के क्षेत्र से गुजरता है, तो एक अंतरराष्ट्रीय अपराध किया जाता है, जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह यह भी स्वीकार करता है कि अफीम के उत्पादन और छोटे हथियारों के व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों से आय एक अंतरराष्ट्रीय 'शो बैंकिंग' प्रणाली के माध्यम से आतंकवादियों के हाथों में जाती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आतंकवाद का कोई

कार्य वास्तव में किया जाए। सम्मेलन यह स्पष्ट करता है कि हर बार जब पैसा किसी राज्य पार्टी के क्षेत्र से गुजरता है, तो एक अंतरराष्ट्रीय अपराध किया जाता है, जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह यह भी स्वीकार करता है कि अफीम के उत्पादन और छोटे हथियारों के व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों से आय एक अंतरराष्ट्रीय 'शो बैंकिंग' प्रणाली के माध्यम से आतंकवादियों के हाथों में जाती है

घटनाक्रम भारत की सुरक्षा के लिए अहम हैं। भारत पिछले दो दशकों से राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि पाकिस्तान सरकार आईएसआई के सहयोग से भारत में आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए अवैध मादक पदार्थों और छोटे हथियारों के व्यापार की आय का उपयोग करती है। पाकिस्तान का उद्देश्य सीमावर्ती राज्यों जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, असम, नागालैंड, मणिपुर और अन्य राज्यों में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं और आर्थिक पिछड़ेपन का शोषण करके देश के सामाजिक ताने-बाने में जातीय विभाजन पैदा करना है। आईएसआई अक्सर इन राज्यों की गरीबी से ग्रस्त मुस्लिम आबादी को, कभी-कभी अन्य लोगों को भी, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए आकर्षित करती है। इसका कारण यह है: (क) आतंकवाद पर भारी व्यय होता है। (बी) पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि वह सरकारी खजाने से बड़ी रकम निकाल सके। (c) गोल्डन क्रीसेंट में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। (d) दक्षिण-पश्चिम एशिया से आने वाली एक किलोग्राम अफीम अमेरिकी बाजार में 210,000 डॉलर में बिकती है।[18] (ई) अंत में, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में गिरफ्तार आतंकवादियों और मादक पदार्थों के तस्करों के चश्मदीद गवाह भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान सरकार भारत में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करती रही है। . इस तथ्य की पुष्टि हालिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड (INCB) की रिपोर्ट से भी हो सकती है, जो रोगियों के लिए एक आवश्यक दवा मॉर्फिन (अफीम का एक व्युत्पन्न) की कमी पर चिंता व्यक्त करती है,[19] 1999 में अफगानिस्तान में अफीम के रिकॉर्ड उत्पादन (4,600 मीट्रिक टन) के बावजूद। इस दवा की कमी का एक कारण भारत में 1998 के दौरान खराब फसल है, जो अंतरराष्ट्रीय दवा उद्योग के लिए अफीम का एक वैध आपूर्तिकर्ता है। अन्य कारक अवैध अफीम व्यापार की वृद्धि है। जाहिर है, कानूनी और आधिकारिक चैनलों की तुलना में अवैध और अनौपचारिक व्यवसाय अधिक आकर्षक है। इस तरह की रिपोर्टें तार्किक निष्कर्ष की ओर भी ले जाती हैं कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार का उपयोग राष्ट्र राज्यों (इस मामले में पाकिस्तान) द्वारा सीमा पार अपने राजनीतिक डिजाइनों का समर्थन करने के लिए किया जाता है।

आईएसआई, सेना और पाकिस्तान सरकार 'ऑपरेशन आतंकवाद' में एक साथ हैं। 1947 से 1999 तक, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, चाहे वह कारगिल में हो या कश्मीर में, पंजाब में कपूरथला में या

असम में कोखराझार में। ये भारत के तीन सीमावर्ती राज्य हैं जहां पाकिस्तान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाड़े के सैनिकों को भारत को अस्थिर करने के लिए प्रायोजित करता है। ऐसी सभी गतिविधियों में पैसा खर्च होता है। खर्च का एक मोटा अनुमान एक महीने में 100 से 150 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट टाइम्स की रिपोर्ट है कि उल्फा एक महीने में लगभग 4 से 6 करोड़ रुपये खर्च करता है।

नारकोटिक ड्रग्स पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत है जहां पाकिस्तान सरकार खुले तौर पर आतंकवाद को प्रायोजित करती है। भारत में आतंकवाद का भूत पैदा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए खर्च के आकलन के लिए कोई प्रामाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, आतंकवादियों और मादक पदार्थों के तस्करों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अकेले आतंकवादियों को भुगतान पर महीने में लगभग 20 से 30 करोड़ रुपये खर्च करता है। उग्रवादियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के दौरान लेखक को बताया गया कि आईएसआई हथियारों और रसद के अलावा रुपये का भुगतान करता है। प्रति माह उग्रवादी नेताओं को 15 से 20 लाख, अनुबंध के आधार पर अफगान मुजाहिदों को 3 से 5 लाख और कश्मीर के दोनों ओर से नई भर्तियों के लिए 15 से 20 हजार। [21] चूंकि सभी वित्तीय लेन-देन नकद में किए जाते हैं, इसलिए इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। लेकिन इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है कि घोड़े के मुंह से जानकारी इकट्ठी की गई?

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बलों को भुगतान पर खर्च का मासिक अनुमान

संख्या भुगतान (रु. प्रति माह) कुल (करोड़ में)

1) उग्रवादी नेता 15 20,000,00 3,00,00,000

2) अफगान मुजाहिद 400 5,000,00 20,00,00,000

3) नई भर्ती 2500 15,000 3,75,00,000

कुल 26,75,00,000

यह जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर एक बहुत ही रूढ़िवादी अनुमान है। यह आंकड़ा मौजूदा अनुमान से कहीं ज्यादा है। इस तालिका का उद्देश्य सिर्फ भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण की उदार प्रकृति को उजागर करना है। यह तालिका भारत में 'ऑपरेशन टेररिज्म' में शामिल लोगों की केवल तीन महत्वपूर्ण श्रेणियों को मासिक भुगतान पर होने वाले खर्च

को दर्शाती है। हथियारों और बुनियादी ढांचे पर खर्च का अनुमान आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसलिए इसे यहां शामिल नहीं किया गया है।

आवश्यक मात्रा में धन उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत पाक-अफगान और अफगान-ईरान सीमाओं पर उत्पादित हेरोइन है। यह क्षेत्र अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक उपभोक्ता वस्तु है। अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट करते समय, डीईए अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अवैध ड्रग्स सीमा पार आतंकवाद और हथियारों के व्यापार से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।[22] एक प्रतिष्ठित पाकिस्तानी विद्वान इकरामुल हक विभिन्न चरणों में ड्रग्स के व्यापार का एक स्पष्ट लेखा-जोखा देते हैं- खेती से लेकर अमेरिकी बाजार में इसकी बिक्री तक।

1. एक एकड़ में खसखस के फूलों से लगभग 7 किलोग्राम कच्ची अफीम का उत्पादन होता है, जिसे किसान लगभग रु. 12,000 से 15,000।
2. दूसरा चरण अफीम का प्रसंस्करण है। एक स्थानीय कारखाने में कच्ची अफीम को हेरोइन में परिष्कृत किया जाता है। इस स्तर पर हेरोइन रुपये में बेची जाती है। 50,000 से 70,000 प्रति किलोग्राम।
3. तीसरे चरण में कोरियर द्वारा हेरोइन की देश से बाहर तस्करी की जाती है। डीलर नेटवर्क में इसकी कीमत लगभग रु. 13,50,000।
4. अंत में, अमेरिका में सड़कों पर बिक्री के लिए हेरोइन को काटकर छोटे बैग में पैक किया जाता है। यह अब 47,00,000 रुपये प्राप्त करता है।[23]

भारत में जब्त प्रमुख दवाओं का अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, 1996-मार्च 2000

वर्ष हेरोइन चरस

मात्रा (KG) मान (RS) मात्रा (KG) मान (RS)

1996 1257 1257 6520 78.89

1997 1332 1332 3281 39.70

1998 655 655 10106 122.28

1999 861 861 3290 39.80

2000 70 70 206 2.49

कुल 4153 4153 23403 283.16

नोट: NCB ने रुपये की दर से हेरोइन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को लेते हुए कीमत पर काम किया है। 1 करोड़ प्रति किग्रा. और हशीश रुपये की दर से। 1.21 लाख प्रति किग्रा. 1996 से मार्च 2000 तक जब्त की गई प्रमुख दवाओं का कुल मूल्य है- रु. 4436.16 करोड़।

कीमत फिर से हेरोइन की शुद्धता पर निर्भर करती है। 80 प्रतिशत शुद्धता के साथ अव्वल नंबर की क्वॉलिटी के लिए 100 रुपए मिलते हैं। 70 से 80 लाख प्रति किलो, जो फिर से शहर से शहर में भिन्न होता है, न्यूयॉर्क सबसे आकर्षक बाजार है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तानी मूल की नंबर 4 गुणवत्ता वाली हेरोइन को चार या पांच बार काटा जा सकता है; घटिया गुणवत्ता के पाउडर के साथ बिना अतिरिक्त लागत के मिलाने पर यह आपूर्ति के लिए एक किलो अतिरिक्त बना सकता है। [24] अब यह न्यूयॉर्क में लगभग एक करोड़ रुपये कमाता है।

मादक दवाओं के व्यावसायिक मूल्य का विश्लेषण तालिका से भी किया जा सकता है, जो 1996 के दौरान अमेरिकी बाजार में उपलब्ध प्रमुख मादक दवाओं की कीमतों पर प्रकाश डालती है।

1996 के दौरान अमेरिका में प्रमुख दवाओं की कीमतें

नारकोटिक ड्रग्स प्राइस रेंज (यूएस $) प्रति किलो।

1) हेरोइन

: दक्षिण पूर्व एशियाई 95,000-210,000

दक्षिण पश्चिम एशियाई 80,000-260,000

दक्षिण अमेरिकी 85,000-185,000

मैक्सिकन 50,000 आगे

2) कोकीन 10,500-36,000

3) कैनबिस/मारिजुआना 200- 4,000 प्रति पाउंड

स्रोत: द नेशनल नारकोटिक्स कंज्यूमर्स कमेटी रिपोर्ट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीईए, इंटेलिजेंस डिवीजन, वाशिंगटन डीसी, 1996।

कीमतों में अंतर मुख्य रूप से अमेरिका के विभिन्न शहरों के मूल्य सूचकांक के कारण है। कानून और व्यवस्था की स्थिति और मांग में वृद्धि के कारण भी दरों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। जैसे ही दवाओं की मांग बढ़ती है, कानून प्रवर्तन एजेंसियां प्रभावी उपाय करती हैं, और जब प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क होती हैं, तो मादक दवाओं की कीमत बढ़ जाती है। दवाओं का अर्थशास्त्र अन्य वस्तुओं से अलग नहीं है। यह 'अवैध टैग' है जो नशीले पदार्थों को अद्वितीय और एक आकर्षक व्यावसायिक उद्यम बनाता है। चीन के कैम्ब्रिज हिस्ट्री ने उन्नीसवीं शताब्दी में अफीम को व्यापार के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु बताया। यह अवैध ब्रांडेड है, लेकिन व्यापार की प्रवृत्ति वही रहती है।

बिड़ला और टाटा सहित भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश व्यावसायिक उद्यमों ने प्रारंभिक वर्षों के दौरान अफीम के व्यापार से पैसा कमाया। कंपनियां लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं और बिना किसी परेशानी के कारोबार कर सकती हैं। विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदली और उस पर 'अवैध टैग' लगा दिया गया। हालांकि यह ड्रग डीलरों की भावना को रोक नहीं सका, लेकिन इससे मुख्य रूप से ड्रग आय के लेन-देन में उनके व्यवसाय में कठिनाई पैदा हुई।

पूरी दुनिया में 'अवैध टैग' की तलवार लटक रही थी और अवैध धन के लेन-देन में शामिल जोखिम उठाने वाले बहुत कम बैंक और वित्तीय संस्थान थे। पैसे की आवाजाही के लिए एकमात्र चैनल नाजायज अंडरवर्ल्ड संचालक थे।

काले धन को वैध बनाना :

अवैध नशीली दवाओं का व्यापार अत्यधिक आकर्षक है और रातों-रात धन और संपन्नता हासिल करने का एक छोटा रास्ता है। पैसा कमाना आसान था, लेकिन धन को अपने गंतव्य तक पहुंचाना मुश्किल। नशीले पदार्थों के तस्करों को नशीले पदार्थों के लेन-देन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जोखिम लेने के लिए बहुत कम बैंक थे, हालांकि ड्रग मनी के मौद्रिक लेनदेन में बैंकों की भागीदारी के उदाहरण हैं। डीलरों को नकदी की आवाजाही के लिए कुछ तरीके तलाशने पड़े। इसलिए, ड्रग सिंडिकेट द्वारा अनगिनत चैनलों का पता लगाया गया और बनाया गया। मौद्रिक लेन-देन के उनके असंगठित लेकिन व्यवस्थित तरीके को लोकप्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में जाना जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग को अवैध गतिविधि से प्राप्त धन के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पहचान को छुपाता है और इसे एक वैध स्रोत से आने वाली संपत्ति में परिवर्तित करता है। नशीले पदार्थों से उत्पन्न बड़ी राशि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का हिस्सा बन गई है। यह कॉर्पोरेट क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काले धन का इस्तेमाल राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह पैसा राजनेताओं को खरीद सकता है, चुनावों के लिए फंड दे सकता है, एक निर्वाचित सरकार को गिरा सकता है, व्यावसायिक उद्यमों को अपने कब्जे में ले सकता है और एक स्थापित राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली को अस्थिर कर सकता है।

मादक पदार्थों की तस्करी से संचित नकदी को विदेशी बैंकों, रियल एस्टेट, होटलों, परिवहन और मनोरंजन व्यवसाय में निवेश के माध्यम से अवैध धन में बदल दिया जाता है। बैंकों से अधिक, निजी वित्तीय संस्थानों ने ड्रग बैरन को अपने वित्त का प्रबंधन करने में मदद की है। स्विट्जरलैंड, हांगकांग, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थाईलैंड उन महत्वपूर्ण देशों में शामिल हैं जो धन शोधन गतिविधियों में एक संगठित तरीके से शामिल हैं। बैंकिंग कानून और कुलीन वर्ग की भव्य जीवन शैली मादक पदार्थों के तस्करों के गुप्त संचालन और मौद्रिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।

वैध वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अच्छा उदाहरण बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल (BCCI) और पाकिस्तान के हबीब बैंक का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग में BCCI की संलिप्तता इस हद तक थी कि इसे बैंक ऑफ क्रुक्स एंड क्रिमिनल्स का उपनाम दिया गया था। लक्ज़मबर्ग में 1972 में एक पाकिस्तानी बैंकर-आगा हसन आबिदी द्वारा स्थापित, BCCI के 70 देशों में व्यावसायिक हित थे और 1980 के दशक तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी। इस बैंक को शुरू में अबू धाबी के शेख जायद बिन अल नाहयान द्वारा वित्तपोषित किया गया था। आबिदी ने विकासशील देशों के लिए एक बैंक या प्रचार के लिए 'तीसरी दुनिया के बैंक' के विचार के साथ खिलवाड़ किया। उनकी दृष्टि ने कई विकासशील देशों को आगे बढ़ाया। यहां तक कि बैंक ऑफ अमेरिका ने बीसीसीआई में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। दस वर्षों के भीतर बैंक काफी आकार में विकसित हो गया था। लेकिन बीसीसीआई द्वारा बड़े पैमाने पर मौद्रिक लेन-देन ने अपने ग्राहकों और कार्यप्रणाली के बारे में संदेह पैदा किया। बैंक ऑफ अमेरिका ने 1986 में अपने ड्रग कनेक्शन की आशंका जताते हुए अपना निवेश वापस ले लिया। ड्रग प्रॉफिट के कई मामले धीरे-धीरे सामने आए। लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशियाई क्षेत्रों के ड्रग सिंडिकेट बीसीसीआई के मुख्य ग्राहक थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रग से होने वाली आय

के साथ बीसीसीआई से संपर्क किया। बैंक के प्रबंधकों अर्थात् मुसेला, अवन, बिलग्रामी, अकबर, बक्सा, नकवी और अन्य ने सिंडिकेट के नेताओं का स्वागत किया। इस बैंक पर पाकिस्तानियों का दबदबा था। अंतत: 1991 में उनका ड्रग लॉन्ड्रिंग नाटक समाप्त हुआ, जब यूएस ग्रैंड जूरी ने प्रबंधकों और अन्य लोगों को धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए लेन-देन में शामिल किया।

दो मामले कानूनी चैनलों के माध्यम से अवैध मौद्रिक लेनदेन के स्पष्ट उदाहरण हैं। पेशेवर तस्करों और गैंगस्टरों के माध्यम से मादक पदार्थों की आय को वैध बनाने के कई अन्य तरीके हैं। इनमें से कई अपराधी केवल नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं और अपने वैश्विक नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए एक समानांतर सरकार चलाते हैं। ये समूह अच्छी तरह से संगठित हैं और लोकप्रिय रूप से 'ड्रग सिंडिकेट' के रूप में जाने जाते हैं। वे विभिन्न माध्यमों से मादक द्रव्यों की धुलाई करते हैं जैसे:-

- बैंक जमा और ऋण या 'स्मर्फिंग'
- दोहरा चालान
- विदेशी व्यापार में निवेश
- रियल एस्टेट में निवेश
- यात्रा और मुद्रा विनिमय एजेंसियां
- हवाला लेनदेन
- मुद्रा तस्करी
- नकदी का वस्तु रूप में रूपांतरण,
- जुआ जोड़ों
- टैक्स हेवन (वीडीएस आदि)

यह उजागर करने की आवश्यकता नहीं है कि दक्षिण पश्चिम एशिया विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में अचल संपत्ति में उछाल दाऊद इब्राहिम (वर्तमान में पाकिस्तान में) और उसके सहयोगियों द्वारा संपत्ति के कारोबार में अभूतपूर्व निवेश के कारण था। मुंबई में मनोरंजन उद्योग का भी यही हाल था, दाउद इब्राहिम एंड कंपनी इस दौरान फिल्मों और संगीत उद्योग के लिए वास्तविक फाइनेंसर के रूप में उभरी। मुंबई में इस तरह के व्यापारिक उद्यमों को वित्तपोषित करके उसके गिरोह ने दस वर्षों तक मुद्रा बाजार पर अपना दबदबा कायम रखा। नशीली दवाओं के तस्करों, अपराधियों, बिल्डरों, फिल्म निर्माताओं और छोटे-मोटे व्यापारिक उद्यमों का नापाक गठजोड़ 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद ही सामने आया।:

निष्कर्ष:

अवैध नशीले पदार्थों और आतंकवादियों का निर्यात और प्रचार इस क्षेत्र में पाकिस्तान की विदेश नीति की आकांक्षाओं के अनुरूप है। इस क्षेत्र का भूगोल और राजनीति दोनों ही पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जलवायु परिस्थितियाँ अफीम की खेती के पक्ष में हैं और राजनीतिक स्थिति पाकिस्तान को भारत में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुजाहिदीन को संगठित करने में मदद करती है। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करने पर जितना खर्च करता है, वह लगभग उतना ही है जितना कि वह अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से उत्पन्न करता है, यानी लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। [28] यह एक वैध तर्क हो सकता है कि यह नशीला पदार्थ है जो भारत को सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने में संलग्न रखने के पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प को बनाए रखता है। इस्लामाबाद का मकसद भारत की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाशक्ति को कमजोर करना है। अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से उत्पन्न कठोर मुद्रा को पंप करके, पाकिस्तान स्थानीय मुद्रा बाजार को परेशान करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की योजना बना रहा है। भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने पाकिस्तान स्थित ड्रग सिंडिकेट के लिए ढेर सारे अवसर भी खोल दिए हैं। देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण के तीन प्रमुख प्रभाव हैं। सबसे पहले, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण में ढील दी जाती है। दूसरा, यह ऋण की उपलब्धता को कम करता है। तीसरा, यह उधार लेने की लागत बढ़ाता है। और चौथा, यह डिपॉजिट पर रिटर्न कम करता है। [29] परिणामस्वरूप मनी लॉन्डर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स अपने अवैध धन को घरेलू मुद्रा बाजार में प्रवाहित करते हैं। बंबई और दिल्ली में रियल एस्टेट बूम के दौरान भारत में ठीक यही हुआ। मूल्य सूचकांक में ऐसी कृत्रिम वृद्धि आर्थिक असंतुलन का कारण बनती है। इसी तरह, हवाला या किसी अन्य अवैध चैनलों के माध्यम से लॉन्ड्रिंग ड्रग मनी भारत को विदेशी मुद्रा आय से वंचित करती है। ये सभी सामूहिक रूप से धीमी प्रक्रिया में देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जो आने वाले समय में महसूस किया जाएगा। इस तरह के अस्थिर करने वाले डिजाइनों का कोई तत्काल प्रभाव नहीं होता है। हालाँकि, यह तथ्य कि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव है, चिंता का विषय है।

भारत को पाकिस्तान में समग्र राजनीतिक-आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में नार्को-आतंकवाद की समस्या का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान धार्मिक राजनीति के नाम पर सैन्य राजनीति, आतंकवाद, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और अपराधीकरण की भूलभुलैया में उलझ गया है। यह सही समय है कि पाकिस्तान के लोग भारत में कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय

के अधिकार की बात करने के बजाय कुछ आत्मनिरीक्षण करें और अपने घर को व्यवस्थित करें। पाकिस्तान सरकार को भी यह समझने की जरूरत है कि उसने भारत के लिए जो जाल बिछाया है, यानी आतंकवादियों और ड्रग तस्करों का जाल, उसका उलटा असर हो सकता है और पाकिस्तान में नागरिक समाज के लिए घातक हो सकता है। अतीत में झांकना व्यर्थ है। 1971 का युद्ध एक इतिहास है जिसे पाकिस्तान सरकार द्वारा दोहराया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि उन्हें यह एहसास हो जाए कि घड़ी की सुई को वापस नहीं लौटाया जा सकता। उन्हें भविष्य की ओर देखना होगा और भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का ढांचा खड़ा करना होगा। जब तक पाकिस्तान खुद यह रवैया नहीं अपनाता, तब तक भारत की सुरक्षा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी

सन्दर्भसूची :

1: स्टीवन आर बेलेंको (संपा.) अमेरिका में ड्रग्स एंड ड्रग पॉलिसी। (कनेक्टिकट: ग्रीनवुड प्रेस. 2000) पीपी. 85-86.

2: यूएनडीसीपी रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति एएफजी/107, एसओसी/एनएआर/811, "1999 में अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन," 10 सितंबर, 1999।

3: इकरामुल हक, पाकिस्तान: फ्रॉम हैश टू हेरोइन, (लाहौर: अनूर पब्लिशर्स, 1991)

4 : उक्त...पी. 35.

5 : नेमीशरण मित्तल, विश्व प्रसिद्ध ड्रग माफिया (नई दिल्ली: फैमिली बुक्स, 1990) पी। 103.

6 : डेविड फिलिप, "गुलाम द ग्रिम" इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 21 दिसंबर, 1996।

7 : न्यूयॉर्क टाइम्स, दिसंबर 1994।

8 : डेविड फिलिप, op.cit.

9 : विलियम वर्नबर्गर, op.cit.

10 : नेशन, 8 दिसंबर, 19994, एशियन स्ट्रैटेजिक रिव्यू, 1994-95, (नई दिल्ली: आईडीएसए, 1995) पीपी 213-16 में सुमिता कुमार की "ड्रग ट्रैफिकिंग इन पाकिस्तान" भी देखें।

11 : विवरण के लिए ब्रायन फ्रीमैंटल, द फिक्स (लंदन: माइकल जोसेफ, 1985

12 : आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 9 दिसंबर, प्रेस विज्ञप्ति, एल/टी/4342/पी1/1216, दिनांक 12 जनवरी, 2000।

13 : नेशनल नारकोटिक्स इंटेलिजेंस कंज्यूमर कमेटी रिपोर्ट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीईए, इंटेलिजेंस डिवीजन, वाशिंगटन डीसी।

14 : अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB), 23 फरवरी, 2000, वियना।

15 : नॉर्थ ईस्ट टाइम्स, जोरहाट, 23 अक्टूबर 1998, पृ. 4.

16 : फेंटन ब्रेस्टलर, द ट्रायल ऑफ ट्रायड्स, (लंदन: वीडेनफील्ड और निकोलसन, 1980) पी। 14

17: रॉबर्ट पॉविस, द मनी लॉन्डरर, (शिकागो: प्रोबस पब्लिशिंग, 1992) पीपी। 191-236।

18 : के सुब्रह्मण्यम, सिक्योरिटी इन चेंजिंग वर्ल्ड (दिल्ली: बीआर पब्लिशिंग कॉम। 1990

19 : उक्त।, पीपी। 191-236।

20 : डगलस आई केह, "इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड क्रिमिनल फाइनेंस" इन ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम, वॉल्यूम। 2, नहीं। 1, स्प्रिंग, 1996, पीपी. 66-80। .

Publish Research Article

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication.

Address:-Ashak Hussain Malik House No-221, Gangoo Pulwama - 192301 Jammu & Kashmir, India
Cell: 09086405302, 09906662570,
Ph No: 01933212815
Email: nairjc5@gmail.com
Website: www.nairjc.com